considerable extent. And I am given to understand that the Government is thinking of closing down the EIA,

I, therefore, request the Minister of Commerce to withdraw the notification and the executive order cited above and to. resist anymove to give further relaxation to quality inspection, and to take adequate steps to transform the statutory status of the organisation to a Central Government Department for a better and efficient functioning.

With these words Sir, I conclude. Thank you.

Ill-effect on the economic structure due to a possible Gulf War

**श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) :** मान्यवर, आज सारी दुनिया एक विचार से बहुत ज्यादा भयभीत हैं कि यदि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया, तो वर्तमान ही नहीं, मानव जाति और इनसानियत का भविष्य और मुस्तकबिल भी खतरे में है।

आज जिस तरह से अमरीका और उसके एलाईज की फौजों ने सऊदी अरब में अड्डा बना लिया है, उससे एशिया और अफ्रीका के जितने भी देश हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने का डर हैं। प्रोपोशन से ज्यादा पांच लाख अमरीकंस और उनके एलाई सोल्जर्स इस वक्त खाड़ी में पड़े हुए हैं। इसी के साथ-साथ 75 लडाकू पानी के जहाज होरमूज के समुद्र में इधर-उधर घूम रहे हैं और लगभग 1,400 लड़ाई के हवाई जहाज वहां पहुंचा दिए गए हैं।

अभी जेनेवा में बातचीत हो रही है आशा की जाती है, शायद कुछ रिजल्ट्स निकले, लेकिन युनाइटेड स्टेटस के होम सेक्रेटरी, श्री जेम्स बेकर, ने जिस तरह से लंदन मे इशारा किया है कि इस बातचीत से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, इससे हमारे ऊपर यह खतरे और बढ़ गए हैं।

भारत के लोगों को, जो हमेशा-हमेशा विश्व शांति में विश्वास रखते हैं, ज्यादा चिंता पूरे देश की, पूरे विश्व की और विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र की है, मान्यवर, आप जानते हैं कि यदि युद्ध हो जाता है तो वह युद्ध इराक, कुवैत और सऊदी अरब के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे एशिय के क्षेत्र को प्रभावित करेगा। और जो आज दुनिया की इकोनोमी जिस चीज से चलती हैं और दुनिया की प्रगति और विकास जिस चीज पर पूरी तरह से निर्भर हैं तेल के सारे कुएं इराक और इरान के विशेष रूप पर जो अमरीका ने उनके ऊपर अपनी मिसाइल फिट की है, वह सब के सब तबाह हो जाएंगे। यदि तेल तबाह हो जाए तब भी एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसके साथ-साथ उन कुओं के जलने से, उनको आग लगने से जो धुंआ उठेगा और जो जहरीली गैसें उठेंगी उससे हमारे यहां का जलवायु, हमारे यहां की क्लाइमेटिक कंडीशज, हमारी कृषि और हमारी सब कुछ जो आर्थिक व्यवस्था हैं वह सारी की सारी चरमरा जाएगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने इस सिलसिले में कोशिश की हैं और उन्होंने ईरान से बात की है कि वह पैट्रोल ज्यादा से ज्यादा हम को दे सके। लेकिन ईरान के कुऐ भी खतरे में हैं। ऐसी सूरत में जबकि हम अपनी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे तेल के निर्यात का करीब 6400 करोड़ रुपये का बजट हर साल भुगतान होता है लेकिन वह अगर यही परिस्थितियां बनी रहीं तो 100 डालर प्रति बैरल तेल का हो जाएगा। और हमारे लिए नेक्सट टू इम्पोसिबल जिसे कहते हैं कि इस सूरत में भुगतान संभव नहीं हो पायेगा ऐसी सूरत में जिस तरह कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं हमारा जो आयात करने का जो तेल का बिल होगा वह लगभग 12,400 करोड़ हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में भारत को अगुवाई करनी चाहिए, पूरी कोशश करनी चाहिए कि युद्ध को

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

जिसको मैं समझता हूं कि कहीं यह तृतीय महायुद्ध की सूरत में परिवर्तित न हो जाए, उसको किसी सूरत में टाला जा सके । इसी के साथ-साथ जो और हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हम किसी तरह से निभा सकें, हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है, मान्यवर, वह इस वक्त डबल डिजिट में है । 11.6 परसेंट है और लगता है कि जो हालात चल रहे हैं उसमें यदि ऐसी कैफियत रही तो यह डबल हो जाएगा । यदि जंग हो जाती है तो यह हमारा जो इन्फ्लेशनरी रेट है वह 30-35 तक पहुंच सकता है ऐसी परिस्थितियों में हमारी योजनायें, हमारे जो आर्थिक संकल्प हैं वे सब से पहले खतरे में पड़ जाते हैं और हम इतने भयंकर तरीके से शीत युद्ध का शिकार हो जाएंगे जिससे कि हमारा उठना मुमकिन नहीं हो पाएगा । हम गुट-निरपेक्ष देशों के अगुआकार रहे हैं, हम यह तो नहीं कहते कि हमारा देश नेता रहा है, लेकिन दुनिया हमें जरूर नेता समझती है । इस सिलसिले में गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने अभी तक कोई ऐसा सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है कोई ऐसा पाजिटव स्टैप नहीं लिया है जिससे उनकी भूमिका का भी पता चल सके । आज जो जनमत है उसको वार के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ, लड़ाई के खिलाफ तैयार करना चाहिए, उस सिलसिले में भी हमारी सरकार और हमारी जनता काफी पीछे रही है । मेरा अनुरोध यह है कि पिछले दो तीन दिनों से इस सदन के अन्दर हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की हैं लेकिन सरकार अभी तक किसी भी वक्तव्य के साथ सदन में नहीं आई है । मैं यह भी अपील करना चाहूंगा कि उस सिलसिले में, शांति स्थापित करने के सिलसिले में, जंग न होने के सिलसिले में, युद्ध को किस प्रकार से रोका जाए और यदि युद्ध हो जाता है तो ऐसी सूरत में हमारा क्या कंटेंजेंसी प्लान होगा, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस सदन को और दोनों सदनों को विशेष रूप से समस्त संसद सदस्यों को कंफीडेंस में, विश्वास में सरकार को लेना चाहिए और एक वक्तव्य के साथ, क्योंकि दो एक दिन के लिए सेशन बढ़ गया है, एक वक्तव्य के साथ सरकार को सदन के सामने आना चाहिए और भरसक प्रयास करने चाहिए कि यह जो जंग है, यह जो युद्ध है वह पूरी तरह से टाला जा सके । निश्चित रूप से यदि हमारी सरकार, हमारा देश आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि कोई सूरत निकल सके ।

धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Dr. J. K. JAIN, not here. Chaudhary Harmohan Singh..

Alleged misuse of urban land (Ceiling and Regulation) Act, 1976

**चौधरी हरमोहन सिंह** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, शहरी भूमि सीमा रोपण अधिनियम के दुरुपयोग के संबंध में आपने कुछ कहने का अवसर दिया उसके लिए मैं आभारी हूं । मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अनुरोध है कि नगर भूमि सीमा अधिनियम अर्बन लैंड सीलिंग कानून 17 फरवरी, 1976 को पूरे देश में लागू हुआ जिसके तहत उत्तर प्रदेश के 12 जिलों, जिला मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, सहानपुर के जिलों में पूर्ण रूप से लागू हुआ । इसके उपरोक्त कानून के तहत प्रदेश के किसानों की 24 करोड़ वर्गमीटर भूमि एकतरफा एक्वायर कर ली गयी है । जबकि पूरे देश में इस कानून का कोई प्रभाव नहीं रहा । दिल्ली जैसी जगहों में 10-12 एकड़ सीलिंग में पहचानी गयी जबकि कानपुर में लगे हुए 252 गांवों में किसानों की 40 लाख वर्गमीटर भूमि लेकर सीलिंग विभाग द्वारा किसानों को नोटिस भेजकर कुर्की वारंट निकालकर किसानों को परेशान किया जा रहा है जिसके कारण किसान विचलित हो उठा है । नगर भूमि सीमा रोपण विभाग किसानों की उपजाऊ भूमि इस कानून के अंतर्गत लेकर 2 हजार रुपए प्रति बीघा मुआवजा दे रहा है तथा किसानों की उसी